



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]
No. 181]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2003/कार्तिक 16, 1925
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2003/KARTIKA 16, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 4 नवम्बर, 2003

सं. टीएएमपी/54/2003-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 49 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, भूखण्ड के किराए-भाड़े और उपकरणों के भाड़ा प्रभारों को, दरमान में, शासित करने वाली शर्तों एवं निबन्धनों को युक्तिसंगत बनाने के लिए पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन प्रदान करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/54/2003-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास

आवेदक

आदेश

(अक्टूबर 2003 के 22 वें दिन पारित)

यह प्रकरण भूखण्ड के किराए-भाड़े और उपकरणों के भाड़ा प्रभारों को, दरमान में शासित करने वाली शर्तों और निबन्धनों को युक्ति संगत बनाने के लिए पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1 पीपीटी ने, निम्नानुसार अपना दरमान संशोधित करने का प्रस्ताव किया है :-

- (i). कार्गो ग्रहस्तन उपकरणों के भाड़ा प्रभारों के मामले में, उपयोगकर्ताओं को न्यूनतम आधी पाली (अर्थात् 4 घंटे) के लिए भाड़ा प्रभारों का भुगतान करना होता है, फिर चाहे उपकरणों का उपयोग केवल 1 घंटे के लिए ही क्यों न किया गया हो। यदि प्रचालनों के दौरान उपकरण में खराबी आ जाए तब भी उपयोगकर्ता से 4 घण्टों का न्यूनतम प्रभार तो लिया ही जाता है। इस विसंगति को दूर करने के लिए और प्रति घंटा आधार पर जलयान संबंधी प्रभारों को युक्तिसंगत बनाने के लिए 9 अप्रैल 2002 को अधिसूचित टीएएमपी के आदेश से इशारा लेते हुए इसने कार्गो ग्रहस्तन उपकरणों के अर्धपाली आधार से प्रति घंटा आधार पर, उपयोग हेतु शर्तों और निबन्धनों को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रस्ताव किया है। तदनुसार, धारा 4(ii) को निम्नलिखित धारे से बदला जाने का और धारा 4 (iii) को अनावश्यक होने के कारण हटा देने का प्रस्ताव है :-

"कार्गो ग्रहस्तन उपकरणों के उपयोग के लिए न्यूनतम प्रभार प्रति घंटा आधार पर होंगे। उपकरण के उपयोग की कुल अवधि, जैसी लॉगबुक में दर्शायी जाएगी, उपकरण के उपयोग के लिए प्रभारों की गणना हेतु आधार होगी।"

- (ii). इस समय, वर्तमान दरमान की धारा 4 (v) के अनुसार, निर्यातक / आयातक / जलयान के मालिक को, जैसा भी मामला हो, पत्तन न्यास के ईन्क्यू बंदरों पर आने वाले जलयानों के लिए, तटीय क्रेनों का उपयोग न करने की एवज में प्रति पाली रु. 1100/- का भुगतान करना होता है। पत्तन के उपयोगकर्ताओं ने इस प्रावधान को रोकने के लिए अभ्यावेदन दिया है क्योंकि उन्हें एक विशेष सुविधा का उपयोग न करने के लिए दण्ड राशि अदा

करने के लिए बाध्य किया जाता है। जलयान वाले पत्तन में उपलब्ध तटीय क्रेनों का उपयोग करने में कम रुचि लेते हैं क्योंकि आजकल जलयानों पर अधिक तेज साइकिल समय वाली उच्च क्षमता वाली क्रेने लगी होती हैं। वर्ष 2002-2003 में, तटीय क्रेनों के उपयोग न करने के लिए पत्तन न्यास की कुल आय 9.41 लाख रुपये थी। यह मानते हुए कि यह धारा तानाशाहीपूर्ण है और इसको जारी रखना पत्तन के सामान्य हित में नहीं होगा, इसने वर्तमान दरमान की धारा 4 (v) को हटाने का प्रस्ताव किया है।

- (iii). वर्तमान दरमान की धारा 3.3.2 के अनुसार पत्तन के उपयोगकर्ताओं से प्रति माह या उसके अंश के आधार पर बके हुए या खुले स्थान / स्टेक यार्ड के लिए लाइसेंस शुल्क लिया जाता है अर्थात् यदि स्थान किसी उपयोगकर्ता को पट्टे पर दे भी दिया गया हो या उपयोगकर्ता द्वारा वह माह के किसी भाग में खाली भी कर दिया गया हो तब भी उपयोगकर्ता को पूरे माह का लाइसेंस शुल्क अदा करना होगा। पत्तन उपयोगकर्ता उन दिनों के लिए भी लाइसेंस शुल्क की अदायगी के प्रति अपनी आपत्ति दर्ज करते आ रहे हैं जिन दिनों वह स्थान वास्तव में उनके कब्जे में था ही नहीं। विशाखापत्तनम् पत्तन में लाइसेंस शुल्क पाक्षिक या उसके भाग के आधार पर लिया जाता है और हालिदया पत्तन में, लाइसेंस शुल्क वार्षिक / मासिक आधार पर लिया तो जाता है किन्तु पत्तन के उपयोगकर्ता अपने अधिपत्य के आरम्भिक और अन्तिम माह में केवल उतने दिनों के लिए ही लाइसेंस शुल्क का भुगतान करते हैं जितने दिन वह स्थान वास्तव में उनके अधिपत्य में रहा। इसको देखते हुए, भूखंड / स्टेक यार्ड / ढकी जगह के अधिपत्य के पहले और अन्तिम माह के सिवाय जिनका लाइसेंस शुल्क अधिपत्य के वास्तविक दिनों के आधार पर वसूल किया जाने का प्रस्ताव है। उद्देश्य के लिए एक माह का अर्थ 30 दिन होगा। जैसाकि एक वर्ष में इस वर्ग के अन्तर्गत बहुत कम मामले आते हैं, इस प्रस्तावित प्रावधान के वित्तीय प्रभाव नगण्य होंगे।

2.2. प्रस्ताव को पीपीटी के न्यासी मंडल द्वारा 22 जुलाई 2003 को हुई बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया था।

2.3. इस पृष्ठभूमि में, पीपीटी ने इस प्राधिकरण से प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है :

- (i) दरमान की धारा 4 (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :

“कार्गो प्रहस्तन उपकरणों का न्यूनतम प्रभार प्रति घंटा आधार पर होगा। उपकरणों के उपयोग की कुल अवधि,

जैसीकि लॉग बुक में दिखाई जाए, उपकरणों के उपयोग के लिए प्रभारों की गणना का आधार होगी।”

- (ii). तटीय क्रेनों का उपयोग न करने के लिए प्रति पाली रु. 1100/- प्रभार लगाने वाली, दरमान की धारा 4(v) हटा दी जाए।

- (iii). दरमान में एक नई धारा 2.4 (xiii) निम्नानुसार सम्मिलित की जाए :-

“पत्तन उपयोगकर्ताओं से भूखण्डों / स्टेक यार्डों / ढकी जगहों के लाइसेंस शुल्क की वसूली अधिपत्य / आबंटन के पहले और अन्तिम माह में अधिपत्य के वास्तविक दिनों के लिए समानुपातिक रूप से।”

3. पीपीटी ने बाद में वर्तमान दरमान के प्रारम्भिक सार भी, जिनमें संशोधन मांगा गया है, प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही, उसके प्रस्ताव में से उठने वाले कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण भी दिया है। पीपीटी ने स्पष्ट किया है कि “हटाया जाना” धारा 4(i) में प्रस्तावित नहीं है (जैसाकि मूल प्रस्ताव में बताया गया है) बल्कि धारा 4(iii) में प्रस्तावित है और धारा 4(ii) को संशोधित प्रस्तावित धारा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. पीपीटी के प्रस्ताव की वर्तमान दरमान के संदर्भ में जांच पड़ताल की गई है और निम्नलिखित स्थिति उभरती है :

- (i). पीपीटी ने उपयोगकर्ताओं प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों का सम्मान करते हुए और पत्तन के सामान्य हित में अपनी ओर से भूखंड के किराए-माड़े और उपकरणों के भाड़ा प्रभारों को संचालित करने वाली कुछ वर्तमान शर्तों और निबंधनों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया है। इस तथ्य पर और इस बात पर भी कि इस प्रस्ताव के वित्तीय प्रभाव नगण्य होंगे, विधिवत विचार करते हुए इस मामले में सामान्य परामर्श की प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है और प्रस्ताव को तीव्रगामी अनुमोदन पर रखने का निर्णय लिया गया है।
- (ii). कार्गो प्रहस्तन उपकरणों के लिए भाड़ा प्रभारों के मामले में, पीपीटी ने कार्गो प्रहस्तन उपकरणों के उपयोग के लिए प्रति घंटा आधार पर न्यूनतम प्रभार लगाने का प्रस्ताव किया है। वर्तमान दरमान के अनुसार, यदि उपकरण केवल एक घंटे के लिए ही उपयोग किया जाता है और यदि उपयोगकर्ता द्वारा मांगे गए उपकरण में प्रचालन के दौरान खराबी आ जाए तब भी उपयोगकर्ता द्वारा न्यूनतम प्रभारों के रूप में आधी पाली (अर्थात् 4 घंटों) के लिए भाड़ा प्रभार का भुगतान किया जाता है। चूंकि प्रस्तावित संशोधन उपयोगकर्ताओं के लाभ में जान पड़ता है और प्रदत्त सेवाओं की सीमा तक ही प्रभार लेने के सिद्धांत का अनुसरण करता है, प्राधिकरण को पीपीटी द्वारा धारा 4(ii) को प्रस्तावित धारा से प्रतिस्थापित करने में कोई झिझक नहीं है।
- (iii). दरमान की धारा 4(iii) में प्रावधान है कि “4 घंटों की आधा पाली के लिए दर ऊपर दिखाई गई पूरी पाली की दर की आधी होगी।” यह धारा आधी पाली के लिए न्यूनतम प्रभार लगाने के प्रावधान से निर्धारित की गई है जिसे प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार धारा 4(iii) भी अनावश्यक हो जाती है और हटा दी गई है।
- (iv). वर्तमान दरमान के अनुसार उपयोगकर्ताओं द्वारा तटीय क्रेनों के उपयोग न करने के लिए प्रति पाली रु. 1100/- की दर से प्रभार लगाए जाते हैं। पीपीटी ने पत्तन में ईक्व बंदरों पर आने वाले जलयानों के लिए इस प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव किया है। हालांकि कुछ पत्तन न्यास उनके द्वारा सृजित सुविधाओं के लिए जब उपयोगकर्ता ऐसी परिसम्पत्तियों का उपयोग न करने का चयन करते हैं, प्रभार लगाते हैं तथापि, पीपीटी ने पत्तन के सामान्य हित में और उपयोगकर्ताओं के अनुरोध पर, इस मद में सजस्व आय को त्यागने का प्रस्ताव किया है। चूंकि इस धारा को हटा देने से पड़ने वाला वित्तीय प्रभाव नगण्य होगा, पीपीटी के वर्तमान दरमान में से धारा 4(v) को हटाया जाता है।

- (v). वर्तमान ब्रॉस के अनुसार, भूखण्डों / स्टैक यार्डों / डके हुए स्थानों के लिए लाइसेंस शुल्क उपयोगकर्ताओं से प्रतिमाह या उसके भाग के आधार पर लिया जाता है। उपयोगकर्ताओं द्वारा उन दिनों के लिए भी जब उन्होंने कब्जा नहीं लिया हो (लाइसेंस शुल्क) अदा करने पर उनकी आपत्तियों को देखते हुए पीपीटी ने उपयोगकर्ताओं से, अधिपत्य के पहले और अन्तिम माह को छोड़कर, जिनके लिए लाइसेंस शुल्क अधिपत्य के वास्तविक दिनों के आधार पर लिया जाएगा, भूखण्डों / स्टैक यार्ड / डके हुए स्थान का लाइसेंस शुल्क मासिक / वार्षिक आधार पर वसूल करने का प्रस्ताव किया है। बताया गया है कि इस प्रस्ताव का वित्तीय प्रभाव नगण्य होगा क्योंकि एक वर्ष में ऐसे मामले बहुत कम होते हैं जो इस वर्ग में आएंगे। ऐसे प्रमाण लगाने के लिए आदर्शरूप में, एक माह में 30 सतत दिन भिन्नता बेहतर रहेगा। तथापि पीपीटी बिल बनाने के उद्देश्य से कैलेंडर माह की गणना को ही जारी रखना चाहता है, अनुमानतः, इससे बिल प्रस्तुत के लिए प्रबोधन में सरलता होगी। जबकि कैलेंडर माह का वर्तमान यूनिट पहले और अन्तिम माह में प्रस्तावित राहत के साथ जारी रह सकता है, पतन को अपने प्रशुल्क की अगली सामान्य समीक्षा में "लगातार 30 दिन के यूनिट (माह) में परिवर्तन करने की सलाह दी जाती है।"
- (vi). जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, इस प्रस्ताव पर परामर्श नहीं लिया गया है क्योंकि प्रस्तावित संशोधन उपयोगकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए हैं। तथापि, यदि कोई उपयोगकर्ता संगठन संशोधनों के किसी प्रतिकूल प्रभाव को उद्घृत करना चाहता है या इस विषय में और अधिक सुधार के लिए कोई सुझाव देना चाहता है तो उसे वैसा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। प्राप्त (की जाने वाली) टिप्पणियों का विश्लेषण करने के बाद, यदि कोई हो, इस समय प्रस्तावित संशोधनों और अधिक सुधार के लिए लिया जा सके।
5. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर प्राधिकरण पीपीटी के दरमान में निम्नलिखित संशोधनों को अनुमोदन प्रदान करता है :-
- (i). कार्गो ग्रहस्तन उपकरणों के लिए भाड़ा प्रमारों से संबंधित धारा 4 के नोट (ii) को प्रतिस्थापित करने के लिए :-
"कार्गो ग्रहस्तन उपकरणों के उपयोग के लिए न्यूनतम प्रमार प्रति घंटा आधार पर होगा। उपकरणों के उपयोग की कुल अवधि, जैसी लॉग बुक में दर्शाई जाएगी, उपकरणों के उपयोग के लिए प्रमारों की गणना का आधार होगी।"
- (ii). वर्तमान दरमान में, कार्गो ग्रहस्तन उपकरण के भाड़ा प्रमारों से संबंधित धारा 4 के नोट (iii) और (v) को हटाना और अनुवर्ती नोटों को तदनुसार पुनः संख्या प्रदान करना।
- (iii). वर्तमान दरमान में लाइसेंस शुल्क से संबंधित धारा 2.4 में निम्नानुसार नोट (xiii) डालना :-
"भूखण्डों / स्टैक यार्डों / डके हुए क्षेत्रों के लिए लाइसेंस शुल्क अधिपत्य / आबंटन के पहले और अन्तिम माह में वास्तविक अधिपत्य के दिनों की संख्या के अनुसार समानुपातिक रूप से वसूल किया जाएगा।"

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2003-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 4th November, 2003

No. TAMP/54/2003-PPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48 and 49 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Paradip Port Trust (PPT) for rationalisation of terms and conditions in the Scale of Rates governing plot rentals and equipment hire charges as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/54/2003-PPT

The Paradip Port Trust

Applicant

ORDER

(Passed on this 22nd day of October 2003)

This case relates to a proposal received from the Paradip Port Trust (PPT) for rationalisation of terms and conditions in its Scale of Rates governing plot rentals and equipment hire charges.

2.1. The PPT has proposed to amend its existing Scale of Rates (SOR) as follows:

- (i). In case of hire charges for cargo handling equipments, the users have to pay minimum charges for half a shift (i.e. 4 hours) even if the equipment is used for an hour. Also in case there is a breakdown of equipment during operations, a minimum charge for 4 hours is realised from the users. To overcome this anomaly and taking a cue from the TAMP Order notified on 9 April 2002 about realisation of vessel related charges on hourly basis it has proposed to rationalise the terms and conditions for use of cargo handling equipments from half shift basis to hourly basis. Accordingly clause 4(ii) is proposed to be replaced by the following clause; and clause 4(iii) will be deleted as redundant:

"Minimum charges for use of cargo handling equipment will be on hourly basis. Total utilization period of equipment as reflected in the log book will be the basis for calculation of charges for use of equipment".

- (ii). Presently, as per clause 4(v) of the existing SOR, the exporters/importers/vessel owners as the case may be are required to pay a charge of Rs.1100/- per shift for non utilisation of shore crane for vessels calling at EQ berths at the Port Trust. The port users have represented to discontinue this provision as they are forced to pay penalty for not using a particular facility. The shippers are less interested to use the shore crane available at the port as now-a-days the ships are fitted with high capacity cranes with faster cycle time. The total earnings of the port trust for non-utilisation of shore crane were Rs.9.41 lakhs during 2002-03. Considering that the clause is authoritarian in nature and its continuance will not be in general interest of the port, it has proposed to delete clause 4(v) of the existing SOR.
- (iii). As per clause 3.3.2 of the existing SOR, license fee for covered and open space/stack yard is recovered from the port users on per month or part thereof basis i.e. even if the space is leased out to a user or vacated by a user in any part of the month, the user is subjected to pay license fee for the entire month. The port users have been objecting to pay for the license fees for the days the space is not actually under their occupation. At the Visakhapatnam Port, the license fees is collected on fortnight or part thereof basis and, at Haldia Port it is collected on yearly/monthly basis but the users pay proportionate license fee for the actual days of occupation during the first and last month of occupation. In view of this it is proposed to recover the license fee from the users on monthly/yearly basis except for the first and last month of the occupation of the plot/stack yard/covered space where the fees will be collected on actual days of occupation. For this purpose, a month will mean a period of 30 days. Since very few cases come under this category in a year, financial implication of this proposed provision will be negligible.

2.2. The proposal was approved by the Board of Trustees of the PPT in their meeting held on 22 July 2003.

2.3. In this backdrop, the PPT has requested this Authority to accord approval to its proposal as follows:

(i). Replace Clause 4 (ii) of the SOR as below:

"Minimum charge for use of cargo handling equipment will be on hourly basis. Total utilization period of the equipment as reflected in the log book will be the basis for calculation of charges for use of the equipment."

(ii). Delete clause 4 (v) of the SOR to discontinue levy of a charge of Rs.1100/- per shift for non-utilisation of shore crane.

(iii). Insert a new clause as 2.4 (xiii) in the SOR as follows:

"Recovery of license fees for plots/ stack-yards/ covered space from the port users proportionately for the days of actual occupation in cases of first and last month of occupation/allotment."

3. The PPT has subsequently furnished relevant extract of the existing SOR in which the amendments are sought; and, clarifications on certain issues arising out of its proposal. The PPT has clarified that deletion is not proposed in clause 4(i) (as stated in its original proposal) but in clause 4(iii) and clause 4(ii) will be replaced by the revised proposed clause.

4. The proposal of the PPT has been examined with reference to the existing SOR and the following position emerges:

(i). The PPT has proposed to rationalise certain existing terms and conditions governing plot rentals and equipment hire charges in deference to representations made by users as also on its own accord in the general interest of the port. Duly considering this fact, and also that the financial implications of this proposal will be negligible, the usual consultative procedure was not followed in this case and has been decided to put the proposal on a fast track approval.

(ii). In case of hire charges for cargo handling equipments, the PPT has proposed to levy the minimum charges on hourly basis for use of cargo handling equipments. As per the existing SOR, minimum charges for half a shift (i.e. 4 hours) are paid by the user in case the equipment is used for an hour as also when there is a breakdown in the equipment requisitioned by the user during operations. Since the proposed modification appears to be for the benefit of the users, and follows the principle of charging only to the extent of services provided, this Authority has no reservations to replace clause 4(ii) with the clause as proposed by the PPT.

(iii). Clause 4(iii) of the SOR provides that "the rate for a half shift of 4 hours will be half of the rate shown above for the full shift". This clause is prescribed with reference to the provision to levy minimum charges for half a shift, which is proposed to be replaced. Hence clause 4(iii) becomes redundant and is also deleted.

(iv). As per the existing SOR, charges are levied @ 1100/- per shift towards non-utilisation of shore cranes by the users. The PPT has proposed to delete this provision for vessels calling at EQ berths at the port. Though some port trusts charge for the facilities created by it when users choose not to use such

assets, the PPT has, in the general interest of the port and on users' request, proposed to forego its revenue earnings on this account. Since the financial impact due to deletion of this clause will be negligible, clause 4(v) of the existing SOR of the PPT is deleted.

- (v). As per the existing clause, license fee for plots/stack yards/covered space is recovered from the users on 'per month or part thereof' basis. In view of the users objections to pay even for the days they have not occupied the premises, the PPT has proposed to recover license fee from the users on monthly /yearly basis except for the first and last month of occupation of the plot/stackyard/covered space where the fees shall be collected on actual days of occupation. The financial implication of this proposal is reported to be negligible as there are very few cases in a year which will come under this category. Ideally, it will be better to reckon 30 consecutive days as a month for levying such charges. Nevertheless, the PPT wants to continue with the calendar month for billing purpose, understandably, for the ease of monitoring raising of bills. While the existing unit of calendar month may continue with the proposed relief in the first and last months, the port is advised to changeover to the unit of consecutive 30 days in the next general revision of tariffs.
- (vi). As has been mentioned earlier, this proposal has not been taken in consultation since the proposed amendments are to provide relief to users. Nevertheless, if any of the concerned user organization wish to point out any adverse impact of the amendments or suggestions for further improvements in this regard, they are given an option to do so within 30 days. After analyzing the comments (to be) received, if any, the amendments made now will be taken up for further refinement.

5. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the following amendments in the PPT Scale of Rates:

- (i). To replace note (ii) of clause 4 relating to hire charges for cargo handling equipment as follows:

"Minimum charges for use of cargo handling equipment will be on hourly basis. Total utilization period of equipment as reflected in the log book will be the basis for calculation of charges for use of equipment".

- (ii). To delete notes (iii) and (v) of clause 4 of the existing SOR relating to hire charges for cargo handling equipment and renumber the succeeding notes accordingly.
- (iii). To insert a note (xiii) in clause 2.4 of the existing SOR relating to license fee as follows:

"The license fee for plots/ stack-yards/ covered space shall be recovered proportionately for the days of actual occupation in cases of first and last month of occupation/allotment."

A. L. BONGIRWAR, Chairman
[ADVT III/IV/143/2003-Exty.]